कानपुर, गुरुवार, 26 फरवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 54, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड गरमागरम नाश्ते के साथ गरम बयानबाजी...>Pg3

शंकराचार्य प्रकरण से सियासी-सामाजिक भूचाल...>Pg12

मूल्यः 2 ₹

माफी नहीं काफी...

NCRT को 'सुप्रीम' नोटिस

एनसीईआरटी की किताब में 'न्यायपालिका' पर टिप्पणी पर सख्ती, नोटिस जारी, अवमानना तक की चेतावनी

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़े अंश पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिना शर्त माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा; यह भी तय किया जाएगा कि ऐसी सामग्री पाठ्यपुस्तक में शामिल कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूली बच्चों तक न्यायपालिका की साख पर प्रश्नचिह्न लगाने वाली सामग्री पहुंचना अत्यंत गंभीर विषय है। अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। ऐसे में पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित सामग्री का स्तर और संतुलन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अदालत ने एनसीईआरटी और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि विवादित अंश हटाने के बावजूद जांच और सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी प्रतियों को तत्काल हटाने के आदेश दिए गए हैं। एनसीईआरटी ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगते हुए विवादित अध्याय हटाने और उसके पुनर्लेखन की जानकारी दी। संस्था ने बयान जारी कर कहा कि यह त्रुटि अनजाने में हुई और किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।

हालांकि अदालत ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना और पूछा कि इस मामले को अवमानना के दायरे में क्यों न माना जाए।

मामला वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी द्वारा उठाए जाने के बाद अदालत के संज्ञान में आया। 24 फरवरी को जारी पुस्तक पर विवाद बढ़ने के बाद स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। एनसीईआरटी ने आपूर्ति रोकने और संशोधित संस्करण 2026-27 सत्र से लागू करने की बात कही है।

यह मामला केवल एक अध्याय तक सीमित नहीं, बल्कि शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा प्रक्रिया, जवाबदेही और संस्थागत संतुलन पर व्यापक बहस का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक नजर में...

- अदालत ने कहा 'शिक्षा व्यवस्था में विश्वास की नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए'
- पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर निगरानी तंत्र की समीक्षा की संभावना
- अवमानना की चेतावनी से संस्थागत जवाबदेही का दायरा बढ़ा
- संशोधित पाठ्यपुस्तक 2026-27 सत्र से लागू करने की तैयारी
- शिक्षा विभाग ने वितरण पर रोक लगाकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई

न्यायपालिका की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों अहम?

- **संवैधानिक आधारः** न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है; उस पर अविश्वास लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
- **स्कूली शिक्षा का प्रभावः** कम उम्र में दी गई सामग्री बच्चों की संस्थाओं के प्रति स्थायी धारणा बनाती है।
- **पूर्व उदाहरणः** सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर संस्थागत गरिमा और अभिव्यक्ति की मर्यादा के बीच संतुलन पर जोर देता रहा है।
- अदालत का संदेश, शैक्षणिक संस्थाएं 'संपादकीय लापरवाही' का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

आगे क्या? संभावित कानूनी और प्रशासनिक असर

- **अवमानना की संभावनाः** यदि अदालत संतुष्ट नहीं हुई तो अवमानना कार्यवाही पर विचार हो सकता है।
- एनसीईआरटी में कंटेंट अप्रूवल और अकादमिक रिव्यू प्रक्रिया की जांच संभव।
- **डिजिटल कंट्रोलः** ऑनलाइन ई-बुक्स और पीडीएफ के लिए तत्काल निगरानी तंत्र मजबूत करने की जरूरत।
- शिक्षा मंत्रालय स्तर पर पाठ्यपुस्तक लेखन, विशेषज्ञ समिति और कानूनी स्क्रीनिंग को अनिवार्य बनाने पर विचार हो सकता है।
- **राजनीतिक बहस तेजः** शिक्षा बनाम संस्थागत गरिमा पर संसद और सार्वजनिक विमर्श में चर्चा की संभावना।

कानूनी परिप्रेक्ष्यः अवमानना बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहती है?
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ङ्ग) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अकादमिक विमर्श, आलोचना और बहस इसी अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

2. लेकिन सीमाएं भी हैं
अनुच्छेद 19(2) के तहत यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। 'न्यायालय की अवमानना' उन आधारों में शामिल है जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि किसी सामग्री से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या जनता का विश्वास डगमगाए, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

3. अवमानना कब मानी जाती है?
न्यायालय की कार्यवाही में बाधा
न्याय के प्रशासन को प्रभावित करना
संस्था की गरिमा को जानबूझकर क्षति पहुंचाना

4. संतुलन की कसौटी
अदालतें आमतौर पर 'संतुलन' की कसौटी पर फैसला करती हैं–क्या सामग्री तथ्यपरक, शोध-आधारित और संतुलित है, या वह संस्थागत अविश्वास को बढ़ावा देती है?

5. इस मामले में क्या संकेत?
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि अदालत यह देखना चाहती है कि क्या पाठ्यपुस्तक की सामग्री अकादमिक आलोचना की सीमा में है या उसने संस्थागत गरिमा की रेखा पार की है।
- यह प्रकरण केवल एक अध्याय का विवाद नहीं, बल्कि इस सवाल का परीक्षण है कि लोकतंत्र में आलोचना की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के बीच रेखा कहाँ खींची जाए।

टीम को देख 9 कुंतल खोया छोड़कर भागे मजदूर

» मिलावटी 15894 किलो सोयाबीन तेल जब्त

» खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर.खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बडी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी खोये और खाद्य तेल को पकडा। पनकी स्टेशन पर इटावा कानपुर पैसेंजर से आए 9 कुंतल खोये की जांच देख मजदूर माल छोड कर भाग गए। बदबूदार खोये को टीम ने नष्ट कराया है। वहीं सचेंडी में छापा मारकर 15894 किलो तेल की जांच में मिलावट पाई गई। खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट ने तेल को जब्त किया है। दोनों स्थानों पर बात करें तो 29 लाख आठ हजार रुपए कीमत के खोये व सोयाबीन तेल पर कार्रवाई की गई है।

सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि होली के मद्देनज़र विभाग सघन अभियान चलाया रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में रजनीश कुमार राय, अजय कुमार मौर्य, सोमनाथ कुशवाहा, अनिल कुमार यादव, संजय कुमार वर्मा और सारिका सिंह शामिल रहीं।

मजदूर खोया छोड़कर फरार

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि इटावा कानपुर पैसेंजर ट्रेन से लाया जा रहा खोया पनकी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। ट्रेन से उतारकर कुछ मजदूर उसे स्टेशन के बाहर ला रहे थे, लेकिन टीम को देखकर मजदूर खोया छोड़कर फरार हो गए। पूछताछ करने पर किसी भी ने उक्त खोये पर अपना दावा नहीं किया।

टीम ने पाया गया कि खोया अत्यंत अनहाइजीनिक स्थिति में गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ सड़क किनारे रखा था। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। टीम द्वारा खोया को गोविंदनगर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट पर ले जाया गया। जहां लगभग 9 कुंतल खोया को नष्ट किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 3,42,000 बताई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों के खोये के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

फूड सेटी ऑन व्हील की जांच में मिली मिलावट

सचेंडी के श्री बिहारी जी ट्रेडर्स में निरीक्षण के दौरान अमृत, माया और सफारी ब्रांड (नेपाल से आयातित)

सोयाबीन तेल भंडारित पाया गया। मौके पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील द्वारा जांच कराने पर मिलावट के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने पर लगभग 15,894 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 25,66,000 रुपए है।

898 किलो बेसन जत

वहीं बिल्हौर स्थित बूंदी निर्माण इकाई पर टीम ने छापेमारा कार्रवाई में पांच नमूने लिए। वहीं 898 किलो बेसन जब्त किया जिसका मूल्य 71840 है।

रिफाइंड सोयाबीन तेल 58 किलो जब्त किया इसका मूल्य 8236 है। वहीं बूंदी वनस्पति और सूजी का नमूने लिए गए हैं।

डफरिन अस्पताल के डॉ. सुधीर कुमार द्विवेदी हुए सम्मानित

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

गुरुग्राम। गुरुग्राम में द मायरा फाउंडेशन द्वारा द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी में आयोजित 'फिजियोकनेक्ट-6' इंटरनेशनल फिजियोथेरेपी सम्मेलन में कानपुर के डफरिन जिला अस्पताल के डॉ. सुधीर कुमार द्विवेदी को फिजियोकनेक्ट लीडरशिप इन फिजियोथेरेपी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मेलन का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत में बहरीन के राजदूत एच.ई. अब्दुलरहमान अलगौद रहे। विशिष्ट अतिथियों में एसीपी अभिलक्ष जोशी और पीएमओ के प्रधान सलाहकार कृष्ण कुमार गौर शामिल हुए। सम्मेलन की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स- फिजियोथेरेपी फॉर ए हेल्दियर टुमॉरो रही। आयोजन अध्यक्ष डॉ. सर्वोतम चौहान के अनुसार, करीब 800 विशेषज्ञों ने भाग लिया और आधुनिक तकनीक व वैश्विक सहयोग पर चर्चा की गई।

रामादेवी से आईआईटी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर पर श्रेय की जंग

शहर कांग्रेस करेगी सांकेतिक पदयात्रा

» जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने दावा किया है कि इस परियोजना की पहल वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। रामादेवी से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तक प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने दावा किया है कि यह परियोजना वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पहल का परिणाम है, जबकि वर्तमान में कुछ जनप्रतिनिधि इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।

कांग्रेस पदाधिकारियों के अनुसार वर्ष 2011 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार कराया गया था और सर्वे की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई थी। उनका कहना है कि इसके बाद यह परियोजना लगभग 15 वर्षों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही।

कानपुर की जरीब चौकी क्रॉसिंग का नजारा...

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जनजागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को शाम 4 बजे रामादेवी चौराहे से गांधी ग्राम गेट तक सांकेतिक पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा का उद्देश्य आम जनमानस को परियोजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराना और कथित रूप से फर्जी श्रेय लेने वालों को आईना दिखाना है।उन्होंने मीडिया संस्थानों से अपील की है कि कार्यक्रम की कवरेज के लिए संवाददाता और फोटो/वीडियो पत्रकारों को भेजा जाए, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके।

गौरतलब है कि रामादेवी से आईआईटी तक का मार्ग शहर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन भारी यातायात दबाव रहता है। ऐसे में एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, परियोजना के क्रियान्वयन और श्रेय को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।

केडीए की बड़ी कार्रवाई: 15 बीघे में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, 60 बीघा और रडार पर

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही तीन अवैध साइटों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यह कार्रवाई जोन-1बी प्रवर्तन दल द्वारा विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डा0 रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।

इन तीनों स्थलों पर विकसित किए जा रहे इंट्री गेट, सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर तथा निर्मित/अर्धनिर्मित भवनों को दो जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया।

पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

अभियान के दौरान अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, सुपरवाइजर अनिल शर्मा, राम औतार, मनोज कुमार, राज कुमार, लाल सिंह तथा थाना बिठूर की पुलिस टीम मौजूद रही। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

तीन स्थानों पर चला बुलडोजर

- ग्राम कटरी ख्यौरा, कानपुर नगर
- निर्माणकर्ता: राम बाबू, शिव दुलारे व अन्य
- रकबा: लगभग 4 बीघा
- बिना स्वीकृति विकसित की जा रही प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण

ग्राम कटरी ख्यौरा, कानपुर नगर

- निर्माणकर्ता: छेदी लाल, नारायण, कुंजी लाल, सोनू व अन्य
- रकबा: लगभग 5 बीघा
- बिना मानचित्र स्वीकृति प्लाटिंग पर कार्रवाई
- आनन्द विहार सोसाइटी, चिरान रोड जंगल वाटर पार्क के पास, कानपुर
- रकबा: लगभग 6 बीघा

60 बीघा और अवैध प्लाटिंग चिन्हित

केडीए अधिकारियों ने बताया कि ग्राम गम्भीरपुर में लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध निर्माण/प्लाटिंग चिन्हित की गई है। इस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ओएसडी डा0 रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लाटिंग कर भोले-भाले लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अवैध कालोनियों में सड़क, नाली, बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं मिलतीं। इससे जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था, पर्यावरण नुकसान और भविष्य में कानूनी विवाद की आशंका रहती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि केवल केडीए से स्वीकृत कालोनियों में ही प्लाट खरीदें। नक्शा और ले-आउट की जांच अवश्य करें। प्लाट खरीदने से पहले केडीए कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें। स्पष्ट है कि अवैध निर्माण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।

समोसे की सियासत: कानपुर में गरमागरम नाश्ते के साथ गरम बयानबाजी

'मुन्ना समोसा' बना राजनीतिक मंच, वादे से वार तक बोले अखिलेश

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर की राजनीति में इस बार मुद्दा सिर्फ बयान नहीं, बल्कि समोसा भी रहा। Akhilesh Yadav अपने पूर्व वादे को निभाते हुए बिरहाना रोड स्थित मशहूर 'मुन्ना समोसा' की दुकान पर पहुंचे तो समर्थकों ने तालियां बजाते हुए कहा–"भैया, आपने वादा निभाया, समोसा खाने जरूर आए!"

दरअसल 12 फरवरी को कानपुर दौरे के दौरान अखिलेश ने पूछा था यहां क्या फेमस है, कचौड़ी या समोसा? जवाब मिला–समोसा। तभी उन्होंने इसे खाने की इच्छा जताई थी। इस बार वह अपनी बेटी अदिति के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे और फिर स्वरूप नगर स्थित घटा पारा रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ विधायक अमिताभ बाजपेई, नसीम सोलंकी, मो. हसन रूमी व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी रहे।

लेकिन समोसे के स्वाद के बीच सियासी तल्खी भी दिखी। इस दौरान अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "बटुक जो हमारे पूजनीय हैं, उनकी चोटी पकड़कर अपमानित किया गया, क्या यह सही है?" उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सिर्फ बयान देते हैं, निर्णय लेने की ताकत नहीं रखते। बुलडोजर कार्रवाई और उन्नाव में लाखों नोटिस के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर ब्राह्मण और आम जनता की अनदेखी का आरोप लगाया।

एनआरसी और एसआईआर जैसे मुद्दों को भी उन्होंने जोड़ा और कहा कि पहले मुस्लिम समाज से कागज मांगे गए, अब हिंदू समाज भी कागज जुटाने को मजबूर है। कानपुर में समोसे की दुकान पर लगी भीड़ ने इस दौरे को अलग रंग दे दिया। जहां एक तरफ गरमागरम समोसे थे, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाज़ी की आंच। साफ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नाश्ता भी संदेश देने का माध्यम बन चुका है।

पीएसआईटी कॉलेज बना पुलिस छावनी, हालात पर कड़ी नजर

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

- सड़क हादसे के बाद छात्र की मौत के बाद हुए हंगामे की जांच जारी,
- परिसर में फिलहाल शांति, कई छात्र-छात्राएं हॉस्टल छोड़कर घर लौटे

कानपुर। थाना सचेंडी क्षेत्र स्थित पीएसआईटी कॉलेज परिसर में बुधवार को छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उपजे तनाव को देखते हुए गुरुवार को भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। प्रशासन ने एहतियातन कैंपस के भीतर और मुख्य गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिलहाल कॉलेज परिसर में शांति व्यवस्था कायम बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक छात्र की बाइक परिसर के निकट खड़ी जेसीबी मशीन से टकरा गई थी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित साथियों ने देर शाम तक हंगामा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और भीड़ को शांत कराया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है–यह देखा जा रहा है कि जेसीबी निर्धारित स्थान पर खड़ी थी या नहीं तथा सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं।

एहतियातन कॉलेज प्रबंधन ने कक्षाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहने की सूचना दी है। कई छात्र-छात्राएं छुट्टी से पहले ही हॉस्टल खाली कर अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। अभिभावकों में भी घटना को लेकर चिंता देखी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कैंपस और आसपास के क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का दावा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, छात्र संगठनों ने मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है।

कानपुर में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन

घंटा-घड़ियाल बजाकर सौंपा ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। ज्योर्तिमठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर अनूठा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घंटा-घड़ियाल और शंख बजाते हुए शंकराचार्य के समर्थन में नारे लगाते नजर आए।

यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर आयोजित किया गया। निर्देशानुसार प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया।

दोपहर लगभग 1 बजे जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं के हाथों में शंकराचार्य के पोस्टर थे और वे फ्रसनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान तथा शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगा रहे थे। घंटा-घड़ियाल और शंखनाद के बीच धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो तथा हर हर महादेव के उद्घोष से परिसर गूंज उठा।

जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने आरोप लगाया कि गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग उठाने के बाद से शंकराचार्य के साथ दमनात्मक व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान उनके अपमान और शिष्यों के साथ अभद्रता की घटनाएं सामने आईं। शुक्ला ने आशंका जताई कि राजनीतिक रंजिश के तहत षड्यंत्रपूर्वक मुकदमा दर्ज कराया गया हो सकता है।ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच गैर भाजपा शासित राज्यों के ईमानदार अधिकारियों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

प्रदर्शन में उमेश दीक्षित, आनंद वर्मा, सतीश दीक्षित, इखलाक अहमद डेविड, तुफैल अहमद, अमित शुक्ला मोनू, राजीव द्विवेदी, बाबूराम सोनकर, राजलक्ष्मी, देवी प्रसाद निषाद, ममता तिवारी, चंद्रमौली बाजपेई, विजय निषाद, अंकित कन्नौजिया, विवेक दीक्षित, सौरभ पांडे, अजीत यादव, राजेंद्र बाल्मीकि, शिवम पटवा, अजय कांत मिश्रा, तिलक चंद्र कुरील, सुशील सोनी, डॉक्टर आर.के. सिंह, राम सिंह, निखिल गुप्ता, नफीस अहमद, फजल खान, मनोज दुबे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा।

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक संगठनों का उग्र विरोध

आज बीएसए कार्यालय पर दिया धरना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के विरोध में जिले के शिक्षक संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न शिक्षक संघ एकजुट होकर चरणबद्ध तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। 26 फरवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा।संयुक्त मोर्चा (टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया) के आह्वान पर जिलेभर के शिक्षक बीते एक सप्ताह से विरोध कर रहे हैं। 22 फरवरी को सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर अभियान चलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 25 फरवरी तक शिक्षकों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते हुए शांतिपूर्ण विरोध जताया।टीईटी कक्षा 1 से 8 तक सरकारी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य अर्हता परीक्षा है, जिसका उद्देश्य बाल विकास और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 से सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के निर्णय के बाद सेवारत शिक्षकों में असंतोष बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई अनिवार्यता थोपना उनके अनुभव और सेवा को नजरअंदाज करना है।राष्ट्रीय स्तर पर टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और महिला शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेशभर में आंदोलन चल रहा है।कानपुर देहात इकाई के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह राजावत ने कहा कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर जबरन टीईटी अनिवार्यता लागू करना न्यायसंगत नहीं है। शिक्षक अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जनपद के सभी शिक्षकों से 26 फरवरी के धरना-प्रदर्शन में शत-प्रतिशत भागीदारी की अपील की है।

धरना के उपरांत जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। यदि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदेशभर के शिक्षक विशाल धरना-प्रदर्शन करेंगे।

शिक्षा व्यवस्था पर उठा बड़ा सवाल

शिक्षक 11 बजे तक नहीं पहुंचे विद्यालय

» बेसिक शिक्षा मंत्री के आदेश बेअसर, बच्चों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार

परिसर के अंदर खेलते बच्चे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बच्चों के भविष्य की नींव माना जाता है, लेकिन जब इसी स्तर पर लापरवाही हावी हो जाए तो व्यवस्था पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कठिका बुझवा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लेटलतीफी ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

जानकारी के अनुसार विद्यालय का निर्धारित समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक है, लेकिन कई शिक्षक सुबह 11 बजे तक भी विद्यालय नहीं पहुंचे। परिणामस्वरूप बच्चे स्कूल के बाहर घंटों धूप में बैठकर अध्यापकों का इंतजार करते रहे। कुछ बच्चे विद्यालय परिसर के बाहर खेलते नजर आए, क्योंकि विद्यालय का ताला तक समय से नहीं खुला। विद्यालय पहुंचे छात्रों ने बताया कि यह स्थिति नई नहीं है। अक्सर वे समय से स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षक देर से आते हैं। ऐसे में पढ़ाई शुरू होने में देरी होती है और उनका कीमती समय व्यर्थ चला जाता है।

सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। उपस्थिति, गुणवत्ता और अनुशासन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर लापरवाही शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना रही है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में यदि जिम्मेदार ही अपने दायित्व से मुंह मोड़ लें तो बच्चों के भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं।

विद्यालय का समय 8:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित है और शिक्षकों को समय से पहुंचने के निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की लेटलतीफी संज्ञान में आई है। संबंधित शिक्षकों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

अजब सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी

सम्पादकीय

विवाहेत्तर संबंधों से दरकता विश्वास

हाल ही में सामने आए एक सर्वेक्षण में, यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जीवन साथी की निगरानी के लिये बड़ी संख्या में डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। तमाम विवाहेत्तर संबंधों की पड़ताल से बड़ी संख्या में शक सही निकल रहे हैं। हालांकि, इस सर्वे के दायरे और उसकी विश्वसनीयता की कसौटी के प्रश्न सामने हैं, लेकिन यह एक कड़वी हकीकत है कि हमारी पारिवारिक संस्था में अविश्वास की सेंध लग रही है। खाओ-पियो मौज करो की पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से वैवाहिक संस्था की शुचिता को आंच आई है। समाज में अलगाव, तलाक व हिंसक प्रतिशोध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रही सही कसर कथित सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जिसने हमारे समाज में वर्जित माने जाने वाले भदेस विषयों को न्यू नॉर्मल बना दिया है। दरअसल, हाल के वर्षों में भारतीय समाज तेजी से संक्रमणकालीन दौर में जा पहुंचा है। कभी जिस रिश्ते को सिरे चढ़ाते वक्त जन्म-जन्मांतर साथ निभाने का वायदा किया जाता था, आज उसी जीवन साथी की निगरानी के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यह दुखद ही है कि जिन जीवन मूल्यों, संयम व शुचिता के रिश्तों के लिये भारत दुनिया में जाना जाता था, वहां आज यौन स्वच्छंदता व विवाहेत्तर संबंधों का दायरा बढ़ रहा है। एक समय था कि भारतीय संयुक्त परिवार की छांव में संयमित व मर्यादित व्यवहार करते थे। बड़ों का अनुशासन मर्यादा की रक्षा करता था। कामकाज का स्वरूप और स्थानीय रोजगार भी जीवन व्यवहार को संतुलित व संयमित करते थे। लेकिन हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव व देश-विदेश में कामकाज के लिये बाहर जाने के बाद व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार करने लगा। यही वजह है कि विदेश में रहने वाले पति या पत्नी के व्यवहार की पड़ताल के लिये डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद लेने के मामले लगातार उजागर हुए हैं। जिसके बाद मुकदमेबाजी, अलगाव व टकराव की खबरें सामने आने लगती हैं।दरअसल, विगत में भारतीय समाज में व्यक्ति के सार्वजनिक व्यवहार को संयुक्त परिवार व समाज संयमित करता था। लेकिन धीरे-धीरे आर्थिक आत्मनिर्भरता के बाद लोगों ने बड़े-बुजर्गों व समाज के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। विगत में हमारी फिल्मों व टीवी निर्माताओं ने दर्शकों की भीड़ जुटाने के लिये हमेशा असामान्य वैवाहिक रिश्तों को अपनी कथावस्तु बनाया। इन असामान्य रिश्तों को इस ग्लैमर के साथ पेश किया जाता रहा है कि कालांतर उसका प्रभाव समाज पर नजर आने लगा। आज तो विदेशी धरती से संचालित इंटरनेट व सोशल मीडिया ने तो असामान्य रिश्तों की पराकाष्ठा दर्शा दी। विडंबना यह रही है कि मीडिया ने भी ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को इतनी तरजीह दी कि समाज के एक तबके में असामान्य रिश्तों को सामान्य माना जाने लगा। एक हकीकत यह भी है कि देश पर तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई होगी, जितनी इंटरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही अपसंस्कृति ने विकृतियां पैदा की। नई पीढ़ी ही नहीं, उम्र दराज लोग भी कामदेव के मोहपाश में बंधे वर्जनाओं को लांघने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बालाओं के मोहपाश में बंधकर गांठ का धन गंवाने वालों में बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है। निस्संदेह, विवाह एक पवित्र बंधन है। जिसका निर्वहन संयम, सहजता, सहयोग, धैर्य और त्याग से ही होता है।

इस्राइल से दोस्ती और गहरी करने का उपक्रम

यशवंत सचदेव

सवाल है, भारत को हेक्सागन समझौते में शामिल होना चाहिए, या नहीं? निर्गुट आंदोलन के फ़ाउंडिंग मेंबर होने के नाते, नई दिल्ली ने हमेशा से कट्टर गुट की पॉलिटिक्स से परहेज किया है।नवंबर, 2025 में, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस्राइल का दौरा किया था और भारत- इस्राइल फ़री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्ट्रक्चर्ड बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस पर साइन किए। वाणिज्य मंत्री के इस दौरे के दौरान 250 से ज़्यादा बी-टू-बी मीटिंग हुईं, साथ ही दोनों तरफ़ के बिज़नेस और सरकारी नेताओं को एक साथ लाने वाले फ़ोरम भी हुए। लेकिन ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि भारत 'हेक्सागन अलायंस' का हिस्सा बनेगा।

पीएम मोदी का दो दिवसीय इस्राइल दौरा 26 फ़रवरी, 2026 को समाप्त हो जायेगा। पूरी दुनिया की नज़र व्यापार से अधिक हेक्सागन समझौते पर है।प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी थी, कि मोदी और उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू भारत-इस्राइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा, साइंस-टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वॉटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकॉनमी और लोगों के बीच उभयपक्षीय संबंधों पर अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। स्टॉकहोम स्थित 'सीपरी' ने 2025 में रिपोर्ट दी थी, कि इस्राइल 2020-24 में दुनिया का आठवां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर था, और भारत इस्राइली हथियारों का सबसे बड़ा अकेला इंपोर्टर था, जो उस समय में इस्राइली एक्सपोर्ट का 34 प्रतिशत था। यह 34 प्रतिशत अब और कितना प्लस होता है, वह नए समझौते से स्पष्ट हो जायेगा।नेतन्याहू ने कहा, 'मेरे सामने जो विज़न है, उसके हिसाब से हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। हेक्सागन ऑफ़ अलायंस का मकसद ऐसे देशों की एक धुरी बनाना है, जो मुस्लिम कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ एक जैसी राय रखते हों। एक नहीं दोनों कट्टरपंथी गुट। पहला, ईरान की सरपरस्ती वाली शिया धुरी, जिस पर हमने बहुत ज़ोरदार हमला किया है। और दूसरी, उभरती हुई कट्टरपंथी सुन्नी धुरी।'हालांकि, किसी भी सरकार ने इस प्लान, या इसके सांप्रदायिक ढांचे का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है। नेतन्याहू की ख्वाहिश है कि इस समूह में भारत, इस्राइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ उदारवादी अरब व अफ्रीकी देश शामिल हों। यह दीगर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके विदेश मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी में है। नेतन्याहू ने जिन तीन देशों का नाम लिया, उनमें से ग्रीस और साइप्रस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। 'आईसीसी' में जो कुछ पक रहा है, उसे काउंटर करने के वास्ते जो कुछ तैयारी नेतन्याहू की है, वो समझ में आने लगा है।किंग्स कॉलेज लंदन में सिक्योरिटी स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग कमेंट करते हैं, कि इस्राइली प्रधानमंत्री शायद अपने आइडिया को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 'हेक्सागन अलायंस' नाटो स्टाइल के समझौते जैसा हो। नेतन्याहू 'शिया एक्सिस', जिसे 'एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस' भी कहा जाता है, के खिलाफ अपनी 'जीत' को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह मध्य-पूर्व में इस्राइली और पश्चिमी असर का विरोध करने वाले ईरान केंद्रित नेटवर्क है। लेबनान में हिज़्बुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है, जिसे लंबे समय से इस इलाके का सबसे ताकतवर नॉन-स्टेट एक्टर माना जाता है। 2024 में इस्राइल द्वारा ज़्यादातर लीडरशिप को खत्म करने से पहले हिज़्बुल्ला तेहरान के साथ जुड़ा हुआ था।इराक में तेहरान कई शिया हथियारबंद समूहों के साथ रिश्ते बनाए हुए है, जिसमें कताइब हिज़्बुल्ला जैसे ग्रुप शामिल हैं। हाल ही में, यमन में, हूथी, एक ज़ैदी शिया आंदोलन, खास तौर पर उभरा है, जिसे तेहरान ने अधोसंरचनात्मक सहयोग, ट्रेनिंग और हथियार दिए हैं। बरअक्स, सुन्नी अतिवादी समूह है।

आर्थिक योगदान व पर्यावरण क्षति का हो मूल्यांकन

पर्यटन की विसंगति

पुष्परंजन

आगन्तुकों की बाढ़ किसी राज्य की सफलता का पैमाना नहीं, बल्कि एक चेतावनी होना चाहिए। यह चेतावनी है संसाधनों के दोहन, अनियोजित शहरीकरण की और उस नीतिगत अंधेपन की है जो श्रद्धा को निवेश समझ बैठा है।उत्तराखंड सरकार के अनुसार गत वर्ष राज्य में पर्यटकों का आगमन 6 करोड़ पार कर गया, जो कुल आबादी से छह गुना अधिक है। 'इंडिया टूरिज्म कम्पोडियम 2025' के आंकड़ों पर गौर करें तो यह आंकड़ा कोई मायावी नहीं है, बल्कि हकीकत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की परिभाषा के आधार पर ही ये आंकड़े तैयार किये गये हैं। उन्हीं आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 64.6 करोड़ और तमिलनाडु में 30 करोड़ से अधिक पर्यटक पधारे थे।

ये भारी-भरकम आंकड़े सरकारी फाइलों में सफलता के प्रमाणपत्र की तरह पेश किए जाते हैं, लेकिन इनकी गहराई में उतरते ही एक गंभीर विरोधाभास भी सामने आता है। अगर किसी प्रदेश में सचमुच आनंद की अनुभूति के लिए इतने पर्यटक आ जायें तो उस प्रदेश का बेड़ापार ही हो जाये! क्या विशाल भीड़ वास्तव में वह 'पर्यटक' है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, या यह केवल एक सांख्यिकीय भ्रम है'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' के मानक 'पर्यटक' की परिभाषा को इतना व्यापक बना देते हैं कि इसमें श्रद्धा और सैर-सपाटे के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर 24 घंटे से अधिक रुकता है, तो उसे पर्यटक माना जाएगा, चाहे उद्देश्य धार्मिक हो या मनोरंजन। इन्हीं मानकों की ओट में भारतीय राज्य कांवड़ियों और साधुओं को भी

'पर्यटक' की श्रेणी में दर्ज कर लेते हैं। यहीं से उस धारणा को चुनौती देने की आवश्यकता है जो संख्यात्मक बहुलता को आर्थिक समृद्धि का पर्याय मान लेती है। वास्तव में पर्यटक और तीर्थयात्री के उद्देश्य और खर्च करने की क्षमता में मौलिक अंतर होता है। पर्यटक होटलों में रुकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में 'लिक्विड कैश' का संचार करता है।

इसके विपरीत, पारंपरिक तीर्थयात्री अक्सर अपना भोजन साथ लेकर चलते हैं और उनकी यात्रा का उद्देश्य मानसिक शांति होती है, न कि आर्थिक उपभोग।'प्लेजर टूर' या आनंदमयी यात्रा ही वास्तव में पर्यटन की वह मूल अवधारणा है जो इसे 'तीर्थाटन' से अलग करती है। पर्यटन का मुख्य आधार 'अवकाश' (लीजर) है, जिसे गिल्बर्ट सिगॉक्स ने एक ऐसी मानवीय गतिविधि माना है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मनोरंजन, ज्ञानवर्धन या स्वास्थ्य लाभ के लिए सामान्य परिवेश का त्याग करता है। तीर्थाटन जहां धार्मिक आस्था, कर्तव्य और मोक्ष की भावना से प्रेरित होता है, वहीं 'प्लेजर टूर' का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शांति, भौतिक सुख और व्यक्तिगत खुशी प्राप्त करना होता है।दरअसल, तीर्थाटन में जहां 'श्रद्धा' सर्वोपरि है, वहीं पर्यटन या 'प्लेजर टूर' जब हम इन दोनों श्रेणियों को एक ही तराजू में तौलते हैं, तो नीतिगत स्तर पर भारी चूक होने की संभावना बढ़ जाती है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां तीर्थाटन का बोलबाला है, वहां की अवसंरचना पर पड़ने वाला दबाव इन करोड़ों नवागन्तुकों की भीड़ से तय होता है, लेकिन उस दबाव को झेलने के लिए मिलने वाला राजस्व उस अनुपात में नहीं होता।

उदाहरण के तौर पर, कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ के लिए प्रशासन को सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था करनी पड़ती , उसका वित्तीय बोझ करदाताओं की जेब पर पड़ता है, जबकि उस भीड़ से होने वाला प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ न्यूनतम होता है।ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम केवल संख्या गिनने के लिए अपनी पारिस्थितिकी और संसाधनों को दांव पर लगा रहे हैंतर्कपूर्ण ढंग से देखें तो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक अवसंरचना भी पूरी तरह भिन्न होती है। एक हाई-वैल्यू पर्यटक को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छता, निजी स्थान और उच्चस्तरीय आतिथ्य की आवश्यकता होती है।

चौड़ीकरण का रास्ता साफ

47 करोड़ से चमकेंगी दो प्रमुख सड़कें

शासन से बजट जारी, सांसद-विधायक व एमएलसी ने किया शिलान्यास

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। क्षेत्र की दो अहम सड़कों के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। करीब 47 करोड़ रुपये की लागत से शिवली-शिवराजपुर और राजेपुर-गदनपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। शासन से बजट स्वीकृत होने के बाद बुधवार को जनप्रतिनिधियों ने विधिवत पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। बुधवार को मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र से सांसद अशोक रावत, बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा उर्फ मोहित सोनकर और एमएलसी अरुण पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर एवं पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

जानकारी के अनुसार शिवली-शिवराजपुर मार्ग की कुल लंबाई लगभग 12.20 किलोमीटर है, जिसके चौड़ीकरण के लिए करीब 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राजेपुर-गदनपुर मार्ग के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मार्ग विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीटी रोड निर्माण के दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी।

पूजा कर सड़क का शिलान्यास करते सांसद, विधायक व एमएलसी ।

शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा होगा और वर्षों से जर्जर सड़कों से राहत मिलेगी। इस दौरान पूर्व उपाध्यक्ष जेपी कटियार, मोहिद्दीनपुर प्रधान राजकुमार सिंह भदोरिया, बार एसोसिएशन बिल्हौर के पूर्व महामंत्री महेंद्र सिंह कुशवाहा, विक्रम मिश्रा, प्रभाकर अवस्थी, रिंकू कटियार समेत कई भाजपाई मौजूद रहे।

शिवराजपुर में नकली मसाले का खेल बेनकाब, दो गिरफ्तार

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मसाले के कारोबार का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक नामी ब्रांड से मिलते-जुलते पैकेट तैयार कर उन्हें बाजार में सप्लाई कर रहे थे, जिससे ग्राहक असली-नकली में फर्क न कर सकें। छापेमारी के दौरान पुलिस को सैकड़ों बंडलों में पैक हजारों पाउच मिले। प्रारंभिक गिनती में करीब 30 हजार पाउच बरामद होने की बात सामने आई है। पैकेजिंग और डिजाइन को इस तरह तैयार किया गया था कि वह असली उत्पाद जैसा लगे। कार्रवाई में बाबूपुरवा निवासी फैज आलम और महाराजपुर क्षेत्र के नवगवां गौतम निवासी रामसागर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में दो स्मार्टफोन, एक की पैड मोबाइल, पहचान पत्र, बैंक कार्ड और कुछ नगदी भी बरामद की गई।

- ब्रांडेड नाम से मिलते-जुलते पाउच बनाकर बाजार में खपाया जा रहा था माल

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नकली माल कहां तैयार हो रहा था, कच्चा माल किससे आता था और किन-किन बाजारों में सप्लाई की जा रही थी, इसकी गहन जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

गैस गोदाम पर जांच करती पुलिस टीम।

सपा विधायक की गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़ 137 सिलेंडर चोरी

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर/चौबेपुरद्य(कानपुर)। चौबेपुर थाना अंतर्गत बेला रोड स्थित प्रतापपुर गांव के पास बने गैस गोदाम में मंगलवार देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। आर्यनगर से विधायक अमिताभ बाजपेई की गैस एजेंसी के गोदाम से 137 सिलिंडर पार कर दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

- सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, भारी वाहन से ले जाए जाने की आशंका

जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह कर्मचारी शाम करीब छह बजे गोदाम बंद कर चले गए थे। बुधवार सुबह जब स्टाफ सिलिंडर लोडिंग के लिए पहुंचा तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जांच करने पर सिलिंडरों की गिनती में बड़ा अंतर सामने आया। कर्मचारियों के मुताबिक गोदाम में पहले 217 भरे और 243 खाली सिलिंडर रखे थे, लेकिन मौके पर 90 भरे और 236 खाली सिलिंडर ही मिले। इस तरह 127 भरे, सात खाली और तीन वाणिज्यिक सिलिंडर गायब पाए गए। एजेंसी कर्मचारी मोहित मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया आशंका है कि सिलिंडर किसी बड़े वाहन में लादकर ले जाए गए हैं। पुलिस आसपास के मार्गों पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है।

तीसरे दिन भी छापेमारी, लेकिन सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर/चौबेपुर(कानपुर)। चौबेपुर क्षेत्र में संदिग्ध इलाज से हुई तीन मौतों के बाद शुरू हुआ स्वास्थ्य विभाग का अभियान तीसरे दिन भी तेज रफ्तार से जारी रहा। लगातार हो रही छापेमारी से अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों और तथाकथित डेंटल सेंटरों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कई संचालक निरीक्षण की सूचना मिलते ही शटर गिराकर मौके से गायब हो गए, तो कुछ केंद्रों पर मरीजों को बीच में ही लौटाया गया।

बुधवार को विभागीय टीम ने पांडेय मार्केट और बैलाही बाजार इलाके में संचालित चार डेंटल क्लीनिकों की सघन जांच की। निरीक्षण के दौरान किसी भी केंद्र पर चिकित्सकीय डिग्री, डिप्लोमा या संबंधित परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र मौके पर उपलब्ध नहीं मिला। टीम ने संचालकों को तीन से चार दिन के भीतर सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि समय सीमा में कागजात प्रस्तुत न करने पर क्लीनिक सील कर दिए जाएंगे और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले की कार्रवाई में एक क्लीनिक को सील किया गया था, जबकि एक अन्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। विभाग का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना पंजीकरण के संचालित किसी भी चिकित्सा केंद्र को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, लगातार हो रही कार्रवाई के बीच स्थानीय नागरिकों में एक अलग तरह की चर्चा भी तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि ये क्लीनिक वर्षों से खुलेआम संचालित हो रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था आखिर कहां थी? क्या समय रहते सख्ती बरती जाती तो तीन परिवारों को अपनों को खोना पड़ता? उनका कहना है कि केवल झोलाछापों पर कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी तय होना चाहिए कि अवैध क्लीनिक इतने लंबे समय तक कैसे फलते-फूलते रहे।

फिलहाल, चौबेपुर और आसपास के क्षेत्रों में चल रही छापेमारी से अवैध चिकित्सा कारोबार पर अस्थायी लगाम जरूर लगी है, लेकिन असली सवाल विभागीय जवाबदेही का है। अब देखना होगा कि यह अभियान कुछ दिनों की कार्रवाई बनकर रह जाता है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की स्थायी पहल साबित होता है।

क्लीनिक पर छापा के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल करते अधिकारी।

- झोलाछाप क्लीनिकों में मचा हड़कंप, कई जगहों पर ताले
- डिग्री, डिप्लोमा और पंजीकरण प्रमाण पत्र मौके पर नहीं मिले
- तीन मौतों के बाद जागा विभाग, निगरानी तंत्र पर उठी उंगलियां

महोबा में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से तीन महिलाओं की मौत

शादी से लौट रहीं महिलाओं को एनएच पर कुचला, दो की हालत गंभीर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों को उजाड़ दिया। कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ कार्यालय के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने पैदल जा रहीं पांच महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

जानकारी के मुताबिक, सभी महिलाएं रात करीब ढाई बजे मीरा पैलेस होटल में एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम खत्म कर अपने घर लौट रही थीं। जैसे ही वे मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के पास पहुंचीं, तभी छतरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी।हादसे में श्यामरानी और भगवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गीता ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, भटीपुरा निवासी तुलसा और राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। श्यामरानी के बेटे संतोष ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ अरुण कुमार सिंह और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन

» नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे, एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में गुरुवार को 'यादव जी की लव स्टोरी' नामक प्रस्तावित फिल्म के विरोध में युवाओं में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।

प्रदर्शन का नेतृत्व श्रीकृष्णा वाहिनी के जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन देते हुए पहाड़ीपुर निवासी समाजसेवी सुनील यादव ने बताया कि यूट्यूबर मृदुल तिवारी व उनकी बहन प्रगति तिवारी द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। उनका आरोप है कि फिल्म में धार्मिक एवं जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले दृश्य दर्शाए गए हैं, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिल्म में दर्शाए गए कथानक से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर कुलदीप सविता, सुधांशु यादव, रेनू यादव, अमन सैनी, अंकित यादव, संजय शुक्ला, नितिन यादव, करन यादव, विवेक राजपूत, सौरभ गौतम, छोटू यादव, प्रधान प्रतिनिधि अरुण यादव, बृजमोहन फौजी सहित कई लोग मौजूद रहे।

भाजपा ने घोषित की मंडल अध्यक्षों की सूची, कहिंजरी व रसूलाबाद में नए चेहरे

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर हो रहा काम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत कानपुर देहात के शेष बचे मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव में अब एक वर्ष से भी कम समय शेष है, ऐसे में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहिंजरी मंडल अध्यक्ष पद पर एक बार फिर राजेश सिंह राजावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह वर्ष 2019 से 2024 तक कहिंजरी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं।

बीच में संगठन ने अन्य कार्यकर्ता को यह दायित्व दिया था। दोबारा नियुक्ति पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों और सरकार की

राजेश सिंह राजावत

उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

वहीं रसूलाबाद मंडल अध्यक्ष पद पर अटल बाजपेयी को नियुक्त किया गया है।

वे करीब 10 वर्ष पूर्व भाजपा से जुड़े थे और लगातार मंडल उपाध्यक्ष

अटल बाजपेयी

के रूप में सक्रिय रहे। मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने संगठन का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बन सके।

घोषणा के दौरान विधायक पूनम संखवार सहित बबलू शुक्ला, अक्षय द्विवेदी, अमरनाथ शर्मा, सानू सिंह गौर, सोनू तिवारी, योगेंद्र पाल, दीपक सोनी, राघव बाजपेई, सचिन गुप्ता, सर्वेश राजपूत, रामआसरे राजपूत, शोभित दीक्षित, गोपी सेंगर, श्यामू चतुर्वेदी, रामू दुबे, संदीप मिश्रा, रीता कठेरिया और अमित सिंह समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन के फैसले पर हर्ष व्यक्त किया। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर दिया जा रहा है और मंडल स्तर पर नई जिम्मेदारियां इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

जनसेवा केंद्र से लौट रही महिला की बाइक की टक्कर से मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जन सेवा केंद्र पर पति के साथ पैसे निकालने गई महिला की सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।शिवली कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर शोभन गांव निवासी गंगा प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी प्रेमलता अपने पति के साथ बैरी सवाई गांव स्थित जन सेवा केंद्र पर खेतों की सिंचाई के लिए पैसे निकालने गई थीं। वापस लौटते समय सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद गंगा प्रसाद तत्काल अपनी पत्नी को उपचार के लिए बारासिरोही गांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाघपुर चौकी प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बाइक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

7 मार्च को रसूलाबाद आएंगे डीएम, संपूर्ण समाधान दिवस में सुनेंगे शिकायतें

तहसील का करेंगे मुआयना, तैयारियों को लेकर महकमे में हलचल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद, कानपुर देहात। आगामी 7 मार्च को जनपद के जिलाधिकारी कपिल सिंह निर्धारित रोस्टर के तहत रसूलाबाद तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनेंगे। जनसुनवाई के बाद वह तहसील परिसर का विस्तृत निरीक्षण भी करेंगे। जिलाधिकारी के आगमन को लेकर तहसील प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

जिलाधिकारी सबसे पहले संपूर्ण समाधान दिवस के अंतर्गत आमजन की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश देंगे। इसके पश्चात वह तहसील के विभिन्न कक्षों, अभिलेखागार और कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे।

जिलाधिकारी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए तहसील परिसर में युद्धस्तर पर साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जहां वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहे हिस्सों में अब रंगाई-पुताई कराई जा रही है। इमारत में लगे मधुमक्खियों के छत्तों को भी हटाया गया है, जिनकी वजह से अक्सर कर्मचारी और फरियादी परेशान होते थे। पुरानी फाइलों को व्यवस्थित कर निर्धारित स्थानों पर रखा जा रहा है। सरकारी अभिलेखों को दुरुस्त करने और रजिस्टरों को अद्यतन करने का कार्य भी तेज कर दिया गया है, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी न रह जाए।

28 फरवरी को पुखरायां में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर, आएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। 28 फरवरी को पुखरायां कस्बे में निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ विकास सचान द्वारा सुलभ होम्योपैथिक के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है, ताकि पुखरायां व आसपास क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।बरसाती पुलिया स्थित सुलभ होम्योपैथिक चिकित्सालय में आयोजित होने वाले इस विशाल शिविर में इंदौर, सागर, कानपुर, भोपाल, पंजाब और आगरा जैसे शहरों से अनुभवी चिकित्सक पहुंचेंगे। शिविर में डॉ. रामलखन सचान, डॉ. संजय झाला, डॉ. पवन चौरसिया, डॉ. सुरेश त्रिपाठी, डॉ. अरमान, डॉ. अमनदीप गुलाटी, डॉ. मोनिका मिश्रा, डॉ. दीपक राणा और डॉ. शिवम सिंह सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। शिविर का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। मरीजों को परीक्षण के लिए पहले पर्चा बनवाना अनिवार्य होगा। इच्छुक मरीज फोन से भी अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं।

सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा शादीशुदा जोड़ों ने दोबारा रचाई शादी

» सिकंदरा में सामूहिक विवाह योजना पर सवालों की बरसात

» बिना अग्नि-फेरे सूचीबद्ध हुए लाभार्थी; जांच के आदेश दिए गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब फर्जीवाड़े के आरोपों में घिर गई है। सिकंदरा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए पहले से शादीशुदा जोड़ों ने दोबारा औपचारिक विवाह कर लाभार्थी सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई जोड़ों के विवाह में न तो विधिवत अग्नि प्रज्वलित की गई और न ही पारंपरिक सात फेरे कराए गए। केवल वरमाला और प्रतीकात्मक रस्मों के आधार पर विवाह संपन्न दिखाया गया। इसके बावजूद संबंधित जोड़ों को योजना का लाभार्थी मानते हुए सूचीबद्ध कर लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर उत्सव जैसा

माहौल था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, लेकिन पात्रता की गंभीर जांच नहीं दिखी। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

पात्रता सत्यापन पर उठे गंभीर प्रश्न

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवार अब भी सरकारी सहायता से वंचित हैं, जबकि अपात्र लोग कागजी प्रक्रिया पूरी कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि आवेदन पत्रों और वैवाहिक स्थिति का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला होगा, बल्कि योजना की मूल भावना के साथ भी अन्याय माना जाएगा।

विभाग ने तलब की रिपोर्ट

मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में अनियमितता या फर्जीवाड़ा सिद्ध होने पर जिम्मेदार अधिकारियों व लाभार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल तथा नगर पंचायत सिकंदरा की अध्यक्ष सीमा पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें जिलाधिकारी कपिल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शासन की मंशा बनाम जमीनी हकीकत

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। ऐसे में यदि जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो यह शासन की मंशा के विपरीत माना जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और लाभार्थी चयन प्रणाली दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है। इस मामले में सीडीओ से फोन पर संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा।

अकबरपुर में 37 किलो गांजा के साथ महिला समेत तीन गिरफ्तार

बस स्टैंड के पास दो पुरुष और एक महिला गांजा बेचने की फिराक में खड़े थे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

(कानपुर देहात) अकबरपुर । होली के मद्दे नजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक की पुलिसिंग चुस्त और दुरस्त देखने को मिल रहा है अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अकबरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने बारा जोड़ पुल के पास स्थित बस स्टैंड से तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 37 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास दो पुरुष और एक महिला गांजा बेचने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर सुबह करीब 8ः30 बजे तीनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवकुश चौहान (23 वर्ष) निवासी ग्राम रठे, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी; बादल सिंह निवासी ग्राम रठे, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी, सुधा सिंह निवासी मोहल्ला शाहीसराय, कस्बा फरह, थाना फरह, जनपद मथुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया और किस नेटवर्क के माध्यम से इसकी सप्लाई की जानी थी। कानपुर देहात जनपद की पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में लिप्त तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा

परिजनों से जानकारी लेती पुलिस

तनाव से जूझ रहे युवक ने फांसी लगाकर दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रुरा थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक दिल्ली में निजी नौकरी करता था और दो महीने पहले घर लौटा था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फंदे से उतारा पंचनामा कराकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू की।मृतक की पहचान रुरा थाना क्षेत्र के दलागांव गांव निवासी अंकित सिंह (28) के रूप में हुई। परिजनों ने बताया है कि अपने कमरे में सोने गया था। रात में उसने छत के पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। कथित तौर पर तनाव में था। सुबह परिजनों ने उसका शव फंदे से लटका देखा। उन्होंने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी आकांक्षा पति की मौत से बदहवास हो गईं। वहीं, मां संगीता और भाई अमित व सागर का रो-रोकर बुरा हाल था। रुरा थाना प्रभारी सुधीर भारद्वाज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रनिया वृद्धाश्रम में देर रात पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

आश्रम परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई को भी देखा, दिए कई निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात । कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद देर रात नगर पंचायत रनिया के चिटिकपुर स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से आश्रम प्रशासन में हड़कंप मच गया।

डॉ. संजय निषाद ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे बुजुर्गों के कमरों में जाकर उनसे संवाद किया और उनका हाल-चाल जाना।

उन्होंने भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए प्रतिबद्ध बनी है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आश्रम परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई का भी बारीकी से जायजा लिया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति की जांच भी रात में की।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आश्रम में रह रहे प्रत्येक बुजुर्ग का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सकों की उपलब्धता चौबीसों घंटे बनी रहे, इस पर विशेष जोर दिया।

औचक निरीक्षण के इस कदम को प्रशासनिक सतर्कता और सामाजिक संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे निरीक्षणों से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

रामपुर में डंपर की टक्कर के बाद कार में लगी आग, महिला सिपाही और मासूम बेटे की मौत

देर रात हादसा, पति और देवर झुलसे; नैनीताल से लौटते समय काशीपुर मार्ग पर हुआ हादसा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 23 वर्षीय महिला सिपाही और उनके दो वर्षीय बेटे की दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसा उस समय हुआ जब परिवार नैनीताल से लौट रहा था। कार को कथित रूप से एक बेकाबू डंपर ने साइड से टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन में आग लग गई।

घटना गंज थाना क्षेत्र में काशीपुर मार्ग के पास आंगा गांव के निकट हुई। टक्कर के बाद कार की पेट्रोल टंकी फटने से आग तेजी से फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

कार में सवार महिला सिपाही लता, उनके पति दान सिंह, दो वर्षीय पुत्र और देवर रवि (22) थे।

पति और देवर किसी तरह वाहन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल रहे, हालांकि वे भी झुलस

गए। महिला सिपाही अपने बेटे को बचाने के प्रयास में कार से बाहर नहीं निकल सकीं। बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी महिला सिपाही ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही, जिसे पुलिस ने वाहन हटवाकर सामान्य कराया।परिवार मिलक क्षेत्र के बेहटरा गांव का निवासी बताया गया है। महिला सिपाही वर्तमान में श्रावस्ती जनपद में तैनात थीं। बताया गया कि कार हाल ही में खरीदी गई थी और परिवार घूमने के लिए नैनीताल गया था। घायल देवर ने अस्पताल में पुलिस को बताया कि लौटते समय अचानक जोरदार टक्कर हुई और वाहन में आग लग गई। पुलिस ने डंपर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

अधिवक्ता के चेम्बर में घुसकर तमंचा ताना, कचहरी परिसर में मचा हड़कंप

» मेटल डिटेक्टर की चेकिंग पर उठे सवाल, साथी वकीलों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अधिवक्ता के चेम्बर में तमंचा लेकर घुस आया और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगा। शोर-शराबा सुनकर पहुंचे अन्य अधिवक्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला न्यू बस्ती सिविल लाइन निवासी अधिवक्ता रोहिताश कुमार सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह दोपहर लगभग 2:30 बजे अपने चेम्बर में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान आयुष गुप्ता नामक युवक चेम्बर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए तमंचा तान दिया। आरोप है कि युवक ने लात-घूंसों से मारपीट भी की, जिससे अधिवक्ता को चोटें आईं। हंगामा सुनकर आसपास के अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी से तमंचा छीनकर उसे पकड़ लिया। बाद में आरोपी के पिता योगेश गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना तत्काल थाना कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस को दी गई।

घटना के बाद कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि न्यायालय के दोनों गेटों पर मेटल डिटेक्टर से सख्त जांच होती है, इसके बावजूद युवक हथियार लेकर अंदर कैसे पहुंच गया, यह गंभीर जांच का विषय है। कोतवाली फतेहगढ़ के प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने

बताया कि आरोपी से तमंचा बरामद कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 730सी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अधिकारियों पर मुकदमे की मांग

» विद्युतीकरण अधूरा, डिवाइडर न होने से बढ़ रहीं दुर्घटनाएं

» जनप्रतिनिधियों ने उठाई जिम्मेदारी तय करने की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद। नव निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 730सी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि शासन-प्रशासन द्वारा एक माह पूर्व सड़क पर लाइटें लगाने और उन्हें चालू कराने के निर्देश जारी किए गए थे, इसके बावजूद अब तक राजमार्ग का विद्युतीकरण पूरा नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र से नाला बघार पुल

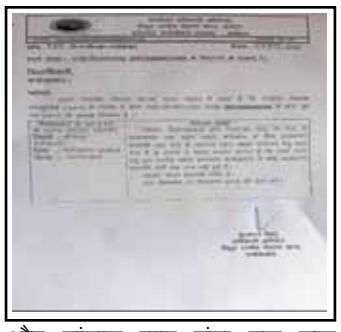

और पांचाल घाट गंगा पुल तक डिवाइडर का अभाव है, जिससे आमने-सामने की टक्कर की घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन दो से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में मौतें भी हो चुकी हैं। रात के समय अंधेरा रहने से स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है।

किसान नेता अशोक कटियार ने आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन द्वारा जारी पत्रों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका

किसान नेता अशोक कटियार

कहना है कि केवल कागजी कार्रवाई कर मामले की लीपापोती की जा रही है, जबकि सड़क पर लगी लाइटें तक नहीं जल रही हैं। उन्होंने दुर्घटनाओं के लिए राजमार्ग प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सुरक्षा मानकों को पूरा कर प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक कार्य नहीं कराए गए, तो जनहित में व्यापक आंदोलन किया

14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बढ़ेंगी सुविधाएं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में निर्माणाधीन 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देशन में चल रहे इस विकास कार्य से तीर्थयात्रियों को परिक्रमा के दौरान अधिक सुविधा, सुरक्षा और आराम मिलेगा। राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।लगभग 40-45 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा मार्ग पर विश्राम गृह, कुण्ड, स्तम्भ, पाथवे, स्टोन बेंच, डस्टबिन और पथप्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इण्टरप्रिटेशन वॉल, शिलालेख और डारेक्शनल साइनेज लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को मार्ग की जानकारी आसानी से

मिल सके। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार, इस परियोजना पर 2124.53 लाख रुपये की लागत आएगी। लक्ष्मी सागर, वैतर्णी, निर्मली, गिरिजा और विभीषण कुण्ड का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। इन कार्यों से परिक्रमा मार्ग का सौंदर्य बढ़ेगा और श्रद्धालुओं को आस्था व आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। साथ ही इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या | जीआईसी ओवरब्रिज मार्ग बंद

पांच मिनट का सफर बना आधे घंटे की परेशानी

जिला अस्पताल और बाजार तक पहुंचना हुआ मुश्किल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में जीआईसी ओवरब्रिज के पास चल रहे निर्माण कार्य के चलते बंद किया गया मार्ग पांच दिन बाद भी नहीं खोला जा सका है। इससे रिकाबगंज और पोस्टमार्टम हाउस की ओर जाने वाला वैकल्पिक रास्ता अत्यधिक दबाव में आ गया है। दिनभर लगने वाले जाम से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है।

मार्ग बंद होने के कारण रूट डायवर्जन किया गया है और जाम से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। संबंधित विभाग से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की अपील की गई है, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके।
- एपी सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात

यह मार्ग जिला महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, बैंक और बाजारों को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। मार्ग बंद होने से मरीजों, कर्मचारियों और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन और सिविल लाइन जाने वाले यात्रियों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। जाम में एंबुलेंस तक फंस रही हैं और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में घंटों का समय लग रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है। रिकाबगंज निवासी रामनारायण ने बताया कि पहले जहां पांच मिनट में सफर पूरा हो जाता था, अब आधे घंटे से ज्यादा समय लग रहा है। अस्पताल जा रही सीमा देवी ने बताया कि मरीज को लेकर जाम में फंसना सबसे बड़ी परेशानी बन गया है।

फर्जी जमानत कांड में सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह को बड़ा झटका

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले में जेल में बंद सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अयोध्या स्थित अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय दीपक यादव की अदालत से पारित हुआ।

मामले में सामने आया कि सहआरोपी उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज अदालत में दाखिल किए गए थे। जांच के दौरान ग्राम प्रधान और जमानतदार के हस्ताक्षर व मोहर फर्जी पाए गए। पुलिस सत्यापन में कूटरचित कागजात की पुष्टि होने के बाद मामला उजागर हुआ।

पूराकलंदर थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, जमानत के लिए नकली दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में पेश किए गए थे। जांच आगे बढ़ने पर राजा मान सिंह की भूमिका भी सामने आई। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। एडीजीसी फौजदारी ने अदालत को बताया कि आरोपी संगठित तरीके से फर्जी जमानत का नेटवर्क चला रहे थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले से साफ है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े इस नेता की कानूनी परेशानियां अभी और बढ़ सकती हैं।

युवक ने की आत्महत्या, पिता की डांट बनी मौत की वजह

पहले हाथ की नस काटी और फिर फंदे से लटककर दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के नहरबाग इलाके में बुधवार शाम करीब चार बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 22 वर्षीय युवक ने पहले हाथ की नस काटी और फिर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक पिता की डांट से क्षुब्ध था, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।

मृतक की पहचान रूपेश उर्फ शिवम शर्मा के रूप में हुई है।

वह मूल रूप से प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सगरा सुंदरपुर का निवासी था और वर्तमान में परिवार के साथ नहरबाग के पास रह रहा था। उसके पिता कमलेश शर्मा चौक में सैलून चलाते हैं। बड़ा भाई योगेश शिक्षण कार्य से जुड़ा है, जबकि रूपेश पढ़ाई कर रहा था।

घटनास्थल पर जांच पड़ताल करती पुलिस

बुधवार दोपहर कमलेश शर्मा दुकान पर चले गए थे। उस समय घर पर रूपेश अकेला था। इसी दौरान उसने यह कदम उठा लिया। जब परिजनों को जानकारी हुई तो आनन-फानन में उसे नीचे उतारकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। कोतवाल अश्विनी पांडेय ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पढ़ाई को लेकर पिता ने युवक को फटकार लगाई थी। इससे वह मानसिक रूप से आहत हो गया और पहले नस काटी, फिर फांसी लगा ली।

300 मीटर की सड़क, 2.37 करोड़ का खेल!

» भीखापुर सीसी रोड टेंडर में 47 लाख का अंतर

» अयोध्या विकास प्राधिकरण पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में विकास के नाम पर खर्च हो रही करोड़ों की राशि अब सवालों के घेरे में है। भीखापुर क्षेत्र में महज 300 मीटर लंबी सीसी रोड और नाली निर्माण पर 2 करोड़ 37 लाख रुपये खर्च किए गए हैं,

जबकि शासन से स्वीकृत और टेंडर की राशि में करीब 47 लाख रुपये का अंतर सामने आया है। यह पूरा मामला अब अयोध्या विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है।सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण ने इस सड़क के लिए शासन को 3 करोड़ 10 लाख 45 हजार रुपये का प्रस्ताव भेजा था, जिसके सापेक्ष 15 फरवरी को 2 करोड़ 84 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। लेकिन टेंडर की लागत 2.37 करोड़ रुपये तय की गई। यानी प्रस्ताव, स्वीकृति और टेंडर–तीनों के आंकड़ों में बड़ा अंतर साफ नजर आता है। यह सड़क देवकाली बाईपास से यशराज होम स्टे और सर्वेश्वरी समूह संस्थान को जोड़ती है। सीमित लंबाई के बावजूद भारी भरकम लागत ने स्थानीय लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। लोगों का कहना है कि इतनी छोटी सड़क पर इतना खर्च समझ से परे है। मामले में जब एई राकेश तोमर से सवाल किया गया, तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए।उन्होंने बची धनराशि से अन्य सड़कें बनवाने की बात कही, लेकिन अंतर की वजह पर चुप्पी साध ली।गौरतलब है कि अयोध्या विजन-2047 के तहत करोड़ों की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं,तीन माह बाद भी नाली निर्माण शुरू न होना, सिस्टम की पोल खोलता है। अब सवाल यह है यह चूक लापरवाही है या सोची-समझी रणनीति? जवाबदेही तय होगी या फाइलों में ही सच दब जाएगा?

प्रयागराज में शंकराचार्य प्रकरण से सियासी-सामाजिक भूचाल

मेडिकल रिपोर्ट ने बढ़ाई तपिश अब कोर्ट करेगा फैसला

स्वराज इंडिया ब्यूरो

प्रयागराज। संगम नगरी में कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े इस बहुचर्चित प्रकरण में नाबालिग पीड़ितों की मेडिकल जांच रिपोर्ट तैयार होकर जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट को बंद लिफाफे में अदालत में पेश किया जाना है, जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया की दिशा और स्पष्ट होगी।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मेडिकल परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में सरकारी अस्पताल में कराया गया। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सीय बिंदु दर्ज किए गए हैं, जिन्हें केस डायरी में संलग्न कर लिया गया है। हालांकि अधिकारी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार

पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता—फोरेंसिक साक्ष्य, बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाण भी जांच का हिस्सा हैं।

मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब एक नाबालिग पीड़ित सामने आया और उसने आरोप लगाया कि अध्ययन के बहाने उसे बुलाया गया, जहां उसके साथ कथित रूप से अनुचित कृत्य हुआ। पीड़ित का यह भी दावा है कि अन्य बच्चों के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं हुईं। पुलिस अब संभावित पीड़ितों की पहचान, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और आवागमन से जुड़े तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है।

जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बच्चों को बाहरी जिलों से लाया गया था और यदि हां, तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। इस एंगल पर विशेष टीम काम कर रही है। उधर, मामले से जुड़े अधिवक्ता को कथित धमकी मिलने से सुरक्षा का मुद्दा भी उठ खड़ा हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए धमकी के स्रोत की पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपित पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार और साजिश करार दिया है तथा अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बचाव पक्ष का कहना है कि आरोपों के पीछे राजनीतिक और वैचारिक कारण हो सकते हैं।

➪ अदालत में पेशी से पहले जांच के दायरे में सामने आए कई नाम

- माघ मेले के दौरान कथित विवाद की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिकायत सामने आई।
- अदालत में प्रार्थना पत्र, शिकायतकर्ता ने न्यायालय का रुख किया।
- अदालत के आदेश पर एफआईआर, नामजद आरोपियों में शंकराचार्य सहित अन्य शामिल।
- पीड़ितों के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की प्रक्रिया शुरू।
- **मेडिकल परीक्षण:** दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा नाबालिगों की जांच।
- **गुरुवार:** मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंपी गई।
- **शुक्रवार:** रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया।
- **अग्रिम जमानत याचिका:** आरोपित पक्ष की कानूनी पहल।

इजरायल में मोदी का कूटनीतिक जलवा

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने संसद में विशेष संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह पदक प्रदान किया।

यह सम्मान भारत-इजरायल के रणनीतिक, रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसे कूटनीतिक हलकों में ऐतिहासिक प्रगति माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा विश्व नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फलस्तीन—दोनों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। इससे पहले वर्ष 2018 में उन्हें फलस्तीन द्वारा 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन' से सम्मानित किया गया था।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि भारत और इजरायल दोनों ने इसकी पीड़ा झेली है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही गाजा क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करते हुए संवाद और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में भारत के विदेश

➪ 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बने नरेंद्र मोदी

मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा इजरायल में भारत के राजदूत जितेन्द्र पाल सिंह भी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक रोचक ऐतिहासिक संयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ उसी दिन जब भारत ने औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी। उन्होंने इसे दोनों देशों के रिश्तों की गहराई का प्रतीक बताया। कूटनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत-इजरायल संबंधों की मजबूती और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत है।

एपस्टीन फाइल्स पर अमेरिका में सियासी घमासान

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर 'कवर-अप' के आरोप, न्याय विभाग ने कहा समीक्षा प्रक्रिया चल रही

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका में कुख्यात दुष्कर्म अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एपस्टीन फाइल्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।

डेमोक्रेट्स का दावा है कि इन दस्तावेजों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े संवेदनशील उल्लेख शामिल हो सकते हैं। आरोपों में एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित शिकायत का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ट्रंप पहले ही इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर चुके हैं।

वहीं अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने आरोपों से इनकार किया है। विभाग का कहना है कि एपस्टीन से जुड़े रिकॉर्ड की विधिसम्मत समीक्षा की जा रही है ताकि किसी दस्तावेज को गलत श्रेणी में डालने या गोपनीय जानकारी के अनावश्यक खुलासे से बचा जा सके।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2019 में दर्ज एक महिला की शिकायत से जुड़े कुछ इंटरव्यू नोट्स और विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। बताया गया है कि संबंधित महिला से एफबीआई एजेंटों ने चार बार पूछताछ की थी, लेकिन सार्वजनिक डेटाबेस में केवल एक सारांश मौजूद है। शेष दस्तावेजों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाउस ओवरसाइट कमिटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने इसे गंभीर मामला बताते

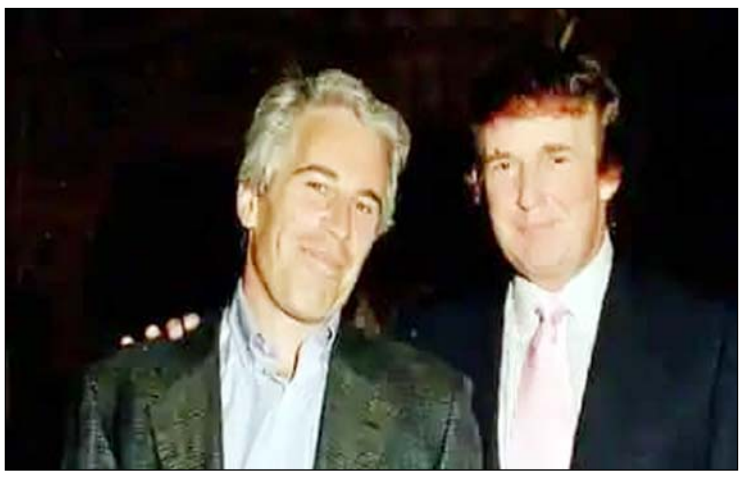

हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर साक्ष्य दबाए गए हैं तो यह पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर आघात होगा। इस बीच, राजनीतिक माहौल में तीखापन बढ़ गया है और मामले ने आगामी चुनावी विमर्श को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

दस्तावेजों की सार्वजनिकता

पारदर्शिता कानूनों के तहत हजारों पन्नों के दस्तावेज पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड अब भी विवाद का विषय बने हुए हैं। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बन चुका है, और आने वाले समय में इसकी जांच और खुलासों पर वैश्विक निगाहें टिकी हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला

जेफ्री एपस्टीन कौन था?
अमेरिकी फाइनेंसर एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप थे।

2019 में गिरफ्तारी और मौत
जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया।

हाई-प्रोफाइल संपर्क
एपस्टीन के संबंध अमेरिका और यूरोप की कई प्रभावशाली हस्तियों से रहे, जिससे मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com